डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इनोवेशन चैलेंज (DEIC)

जिला कार्यान्वयन एसओपी (SOP)

जनवरी 2026

LiftEd Transforming Foundational Literacy and Numeracy

विषय सूची

भाग (क) – डीईआईसी की पृष्ठभूमि और संदर्भ:

01 – डीईआईसी का परिचय

02 – सीमाएं और रचना (डिज़ाइन) के प्रमुख सिद्धांत

भाग (ख) - जिला कार्यान्वयन एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया)

01 – प्रमुख हिस्सेदारकों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ

02 – जिले के चयन करने की प्रक्रिया *(ऑनबोर्डिंग)*

03 – डेटा संग्रहण और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक *(केपीआई)* ढांचा

04 – जिला मान्यता ढांचा *(डीआरएफ)*

05 – जिला मार्गदर्शन व्यवस्था

भाग (अ) - डीईआईसी की पृष्ठभूमि और संदर्भ

(01) डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इनोवेशन चैलेंज (DEIC)

लिफ्टएड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इनोवेशन चैलेंज (DEIC) एक चुनौती – आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म–नवाचार को बढ़ावा देकर, आँकड़ा–संचालित शासन को प्रोत्साहित करके और सभी जिलों में प्रदर्शन सुधारों को पुरस्कृत करके झारखण्ड में FLN प्रतिफलों के लिए गति का निर्माण करना है। DEIC का कार्यान्वन JEPC द्वारा लिफ्टएड DEIC कंसोर्टियम के सहयोग से किया जाएगा, जिसमें मातृ ट्रस्ट, पोर्टिकस फाउण्डेशन, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, डालबर्ग एडवाइजर्स और रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट शामिल है।

डीईआईसी का ध्येय सरकारी तंत्र में कार्रवाई को प्रोत्साहित कर राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन लाना हैं, जिसके परिणाम इस प्रकार हैं :–

1. **अल्पकालिक और दीर्घकालिक में उच्च FLN प्रतिफल –** DEIC झारखण्ड के जिलों को प्रमाणित उपायों के कार्यान्वयन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार एवं मान्यता का लाभ उठाकर FLN प्रतिफलों में सुधार के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
2. **जिला अधिकारियों की बेहतर क्षमता –** DEIC के तहत् झारखण्ड में जिला अधिकारी (जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक) विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे और अधिगम यात्राओं में भाग लेंगे जिससे उनकी नवोन्मेषी सोच, नेतृत्व और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता का निर्माण होगा और प्रशासनिक क्षमता में सुधार होगा। यह राज्य की नींव को मजबूत करेगा और इसे स्वतंत्र रूप से DEIC मॉडल को अपनाने और संचालित करने में सक्षम बनाएगा।
3. **बेहतर FLN आँकड़ा संग्रहण और विश्लेषण प्रणाली –** DEIC झारखण्ड राज्य सरकार को FLN प्रतिफलों के आँकड़ा अवसंरचना एवं संग्रहण प्रणाली की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता को परिष्कृत करने तथा सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करेगा और आँकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार हेतु राज्यव्यापी स्तर पर इनके अंगीकरण में तेजी लाएगा।
4. **मूल्यांकन की सुविधा –** यह चुनौती उन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) की पहचान करने में सहायता करके राज्य की मूल्यांकन क्षमता का निर्माण करेगी जो FLN सुधार के सर्वोत्तम संकेतक हैं और उनका मूल्यांकन करने के लिए राज्य की क्षमता को विकसित करेगी।
5. **झारखण्ड एक आदर्श राज्य बनेगा –** झारखण्ड अन्य राज्यों के लिए एक FLN चुनौती अपनाने हेतु प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, जिससे यह एक अग्रणी के रूप में स्थापित होगा। प्रचार–प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों/भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे–आकांक्षी जिले) में इसके अनुभव में सीखने के लिए अधिक फाउण्डेशनों, परोपकारी लोगों और अन्य निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है।

(02) दायरा और रचना (डिज़ाइन) के सिद्धांत

परिधि	विवरण

व्याप्ति	राज्य के सभी 24 जिले
समय–सीमा	3वर्ष–शैक्षणिक सत्र 2025–26 से 2027–28 तक
कार्यान्वयन निकाय	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद
सहयोगी संगठन	संस्थापक भागीदारः मैत्री ट्रस्ट और पोर्टिकम फाउंडेशन; कार्यक्रम प्रमुखः ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट; प्रदर्शन प्रबंधनः डालबर्ग एडवाइजर्स; और तकनीकी भागीदारः रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट
लक्षित हितधारक	1. जिला शिक्षा अधिकारी (DEOs), जिला शिक्षा अधीक्षक (DSEs) और सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ADPOs) 2. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEos), प्रखंड संसाधन सेवी और संकुल संसाधन सेवी 3. प्रधानध्यापक और शिक्षक
मुख्य विषय	बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता + विद्यालय का परिवेश

DEIC का उद्देश्य, जिला–स्तरीय नेतृत्व को उनके प्रदर्शन पर आँकड़ा–समर्थित साक्ष्य के साथ सशक्त बनाकर, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता और विद्यालय के परिवेश को बेहतर बनाना है। डीईआईसी को तीन मूल सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है – मोमेंटम (गति), विजिबिलिटी (दृश्यता) और गाईडेंस (मार्गदर्शन)।

(क) मोंमेंटम (गति) :–

DEIC को जिलों के बीच गति को निर्माण करने और उसे बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए मान्यता को मापने योग्य, सत्यापन योग्य और आँकड़ा–समर्थित प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जिला प्रशासनों की ऊर्जा को एफएलएन और विद्यालय के परिवेश संबंधी स्पष्ट प्राथमिकताओं की ओर निर्देशित करना है, साथ ही पारदर्शी और आँकड़ा–संचालित तरीके से प्रगति को प्रोत्साहित करना हैं।

इसमें सभी प्रमुख जिला पदाधिकारी (जिला कलेक्टर, डीईओ, एडीपीओ, डीएसई) शामिल होंगे, साथ ही सभी स्तरों (प्रखंड, विद्यालय, आदि) पर किए गए प्रयासों को तिमाही और वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाएगी। जिले के प्रदर्शन को मापने के लिए डीईआईसी उन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators) को ट्रैक करेगा जिन्हें एफएलएन और विद्यालय के परिवेश के लिए प्राथमिकता दी गई है और उनका मूल्यांकन डीईआईसी के जिला मान्यता फ्रेमवर्क (District Recognition Framework) का उपयोग करके किया जाएगा।

क. 1 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) फ्रेमवर्क :–

जिलों का मूल्यांकन एक संरचित फ्रेमवर्क के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 17 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) शामिल हैं (जो इनपुट, कक्षा निर्देश और सामुदायिक भागीदारी को कवर करते हैं) तथा 4 परिणाम संकेतक हैं (जो छात्र सीखने और विद्यालय के परिवेश को मापते हैं)। यह आँकड़ा eVV, ऐप UDISE+ डेटा और अन्य स्रोतों से एकत्र किया जाएगा। KPI फ्रेमवर्क को देखी गई प्रगति ओर जमीनी हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर वार्षिक रूप से परिष्कृत किया जा सकता है ताकि इसकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

क. 2. जिला मान्यता फ्रेमवर्क :–

प्रत्येक KPI को 'जिला मान्यता फ्रेमवर्क' के माध्यम से मापा और रैंक किया जाएगा, जिसकी गणना तिमाही और वार्षिक दोनों आधार की जाएगी। इस फ्रेमवर्क से मान्यता प्राप्त करने वाले जिलों के लिए तिमाही और वार्षिक आधार पर एक संरचित पुरस्कार प्रणाली स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति और निरंतर प्रयासों को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्ट नवाचारों वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मान्यता तंत्र में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- प्रदर्शन दर्शाने वाले सार्वजनिक लीडरबोर्ड
- उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों और शिक्षकों के लिए केस प्रोफाइल
- सहकर्मी–शिक्षण को सक्षम करने के लिए सीखने की यात्राओं के अवसर
- प्रेरणा को बढ़ावा देने, उपलब्धियों का जश्न मनाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा निरंतर सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई मान्यता के अन्य रूप।

(ख) विजिबिलिटी (दृश्यता) :–

'विजिबिलिटी' का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जिला प्रशासनों को उनके प्रदर्शन पर पारदर्शी और समय पर आँकड़ों तक पहुँच प्राप्त हो। यह निरंतर निगरानी, विश्वसनीय मूल्यांकन और सुधार के कार्रवाई योग्य अंतदृष्टि पर केंद्रित है। दृश्यता स्थापित करने के लिए डीईआईसी eVV पर एकत्र किए गए KPIs के आँकड़ों का उपयोग करेगा और उन्हें जिलों के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट या स्कोरकार्ड पर प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही एफएलएन और विद्यालय के परिवेश के परिणामों पर वार्षिक मूल्यांकन भी जिलों के लिए परिणाम–स्तर पर प्रगति की दृश्यता प्रदान करते हैं।

ख . 1 विद्यावाहिनी (eVV) ऐप के माध्यम से आँकड़ा संग्रहण :–

राज्य द्वारा विकसित एक आईसीटी–आधारित प्लेटफॉर्म, ई–विद्यावाहिनी (eVV) एप्लिकेशन, डीईआईसी के तहत वास्तविक समय में विद्यालय–स्तरीय आँकड़ा संग्रहण के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में काम करेगा। आँकड़ों को ब्लॉक संसाधन सेवी (BRPs) और संकुल संसाधन सेवी (CRPs) द्वारा नियमित विद्यालय निगरानी यात्राओं के दौरान तथा शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों द्वारा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल सर्टिफिकेशन और शिक्षक आवश्यकता मूल्यांकन तथा 'मेरा निपुण विद्यालय' जैसे अन्य राज्य कार्यक्रमों से स्वतंत्र मूल्यांकन का उपयोग भी प्रासंगिक डीईआईसी KPIs के लिए किया जाएगा।

ख . 2. वार्षिक तृतीय–पक्ष मूल्यांकन :–

जिले के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करने के लिए, स्वतंत्र तृतीय –पक्ष मूल्यांकन वाार्षिक रूप से आयोजित किए जाएँगे। इस मूल्यांकन में एफएलएन अधिगम प्रतिफल और विद्यालय का परिवेश/समग्र बाल विकास के परिणाम शामिल होंगे। यह मूल्यांकन, पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान जिले के प्रदर्शन की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए तिमाही निगरानी आँकड़ों (आउटपुट) पर आधारित होगा। प्रदर्शन के रूझानों, मुख्य निष्कर्षों और सुधार के क्षेत्रों को प्रस्तुत करते हुए, जिला–स्तरीय और राज्य–स्तरीय रिर्पोट तैयार की जाएँगी और हितधारकों के साथ साझा की जाएँगी।

ख . 3. मासिक स्कोरकार्ड (प्रगति की दृश्यता) :–

जिलों को सभी क्म्प्ब् झच्े पर प्रदर्शन का सारांश देने वाले मासिक स्कोरकार्ड होंगे। इनमें जिले के वर्तमान प्रदर्शन, पिछले चक्र से हुई प्रगति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सहकर्मी बेंचमार्क पर आँकड़े शामिल होंगे।

(ग) मार्गदर्शन :–

डीईआईसी के दौरान, जिलों को उनके झच् प्रदर्शन के आधार पर लक्षित, रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें अपनी प्रगति को समझने, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और बनाए रखने या बढ़ाने योग्य प्रथाओं को पहचााने में मदद मिल सके। साथ ही, वे लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जेईपीसी और डीईआईसी प्रदर्शन प्रबंधन इकाई से सलाहकार इनपुट करेंगे।

ग. 1 मार्गदर्शन गतिविधयाँ :–

जिलों के लिए उपलब्ध मार्गदर्शन तंत्र के उदाहरणों में शामिल हैं :–

- प्रदर्शन के रूझानों को ट्रैक करने और त्वरित सुधारात्मक उपायों पर चर्चा के लिए मासिक समीक्षा बैठकें।
- प्रगति की गहराई से समीक्षा करने और उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए जिला नेतृत्व और जेईपीसी/पीएमयू टीम के बीच द्वि–वार्षिक 1:1 रणनीतिक बैठकें।
- तकनीकी जानकारी प्रदान करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और जिलों के बीच सहकर्मी–शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में कार्यशालाएँ और सीखने के सत्र ।

ग. 2 सीखने के संसाधन :–

सीखने के संसाधन मार्गदर्शन गतिविधियों के अलावा अन्य राज्य सहायता संसाधन भी हैं जो जिलों को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध है :

- **सीखने के संसाधन** : इसमें गाइड, केस स्टडी, एफएलएन प्राइमर और नेतृत्व मॉडयूल शामिल हैं, जो डीईआईसी की सीख और अन्य राज्यों तथा संदर्भों की सिद्ध प्रथाओं, दोनों से लिए गए हैं।
- **विशेषज्ञों तक पहुँच :** जिलों को निरंतर या ऑन–डिमांड सहायता के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल उपलब्ध कराया जा सकता है। पैनल में गैर–सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, पूर्व जिला अधिकारी आदि शामिल हो सकते हैं।

भाग ख – जिला कार्यान्वयन एसओपी

01. प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ :

DEIC का नेतृत्व झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) द्वारा किया जाएगा और इसे DEIC PMU के तकनीकी सहयोग से, जिलों तथा प्रखण्डों में समन्वित कार्रवाई के माध्यम से कार्यन्वित किया जाएगा। प्रत्येक हितधारक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं :

हितधारक	प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
JEPC	• DEIC के लिए दिशानिर्देश, रणनीति और कार्यान्वयन ढ़ांचा जारी करना। • ई–विद्यावाहिनी (eVV) पर हितधारक मॉड्यूल को परिष्कृत करके एक मजबूत आँकड़ा–संग्रह प्रक्रिया को लागू करना। • DEIC के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए राज्य–स्तरीय DEIC समीक्षा आयोजित करना, प्राथमिकताएँ निर्धारित करना और जिलों तथा प्रखण्डों को निर्णय संप्रेषित करना। • जिलों और परिवर्तनकर्ताओं (Changemakers) की तिमाही और वार्षिक मान्यता सुनिश्चित करना। • अन्य राज्य पहलों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना और कार्यक्रम कैलेण्डर को संरेखित करना।
जिला प्रशासन	• जिला FLN कार्यसूची और मासिक समीक्षा अनुसूची के भीतर DEIC को एकीकृत और प्राथमिकता देना। • एडीपीओ (ADPOs) को DEIC के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित करना और कार्यक्रम की तैयारी सुनिश्चित करना। • KPIs, आँकड़ों की गुणवत्ता और परिणामों के उपयोग पर प्रखण्ड के अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना।

	• उपायुक्त की अध्यक्षता में DEIC के तहत् जिला स्तरीय प्रदर्शन पर मासिक समीक्षा आयोजित करना। • सुधार के क्षेत्रों और जिले की प्राथमिकताओं की पहचान करना, परिणामों में सुधार के लिए नवाचार के अवसरों का पता लगाना। • स्थानीय नवाचारों को पहचानना और राज्य स्तरीय मान्यता तथा स्पॉटलाइट के लिए मामलों को नामांकित करना, जिलों के भीतर सिद्ध प्रथाओं को बढ़ाना।
ब्लॉक प्रशासन	• जिले की प्राथमिकताओं को स्पष्ट क्लस्टर और स्कूल लक्ष्यों के साथ एक ब्लॉक कार्यान्वयन योजना में बदलना। • प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (Block Education Exetension Officer) की अध्यक्षता में DEIC के तहत् प्रखण्ड स्तरीय प्रदर्शन पर मासिक समीक्षा आयोजित करना। • प्रत्येक माह ई–विद्यावाहिनी पर BRPs, CRPs और शिक्षकों द्वारा विद्यालय–स्तरीय आँकड़ों का पूर्ण और समय पर संग्रहण सुनिश्चित करना। • DEIC के प्रदर्शन पर क्लस्टर–स्तरीय समीक्षा आयोजित करना, कार्रवाईयां जारी करना और उनके समापन को ट्रैक करना। • KPIs, आँकड़ों की गुणवत्ता और परिणामों के उपयोग पर क्लस्टर अधिकारियों और स्कूल टीमों की क्षमता का निर्माण करना। • प्रखण्ड–स्तरीय नवाचारों और परिवर्तनकर्ताओं की पहचान और दस्तावेजीकरण करना। जिला और राज्य स्तरीय मान्यता के लिए नामांकित करना, क्लस्टरों के बीच सहकर्मी–शिक्षण को सक्षम बनाना।
PMU	• DEIC के लिए तकनीकी और कार्यक्रम–प्रबंधन की रीढ़ के रूप में कार्य करना। • जिलों और प्रखण्डों के लिए एसओपी (SOPs), उपकरण, टेम्पलेट और उन्मुखीकरण सामग्री विकसित करना और बनाए रखना। • राज्य, जिला और प्रखण्ड स्तर पर अधिकारियों को उन्मुख करना। • आँकड़ों की गुणवत्ता की निगरानी करना और आँकड़ा संग्रहण तथा सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शोधन की सिफारिश करना। • DEIC पर जिला और प्रखण्ड के प्रदर्शन और संबंधित डैशबोर्ड को दर्शाने वाले मासिक स्कोरकार्ड तैयार करना। • जिला मार्गदर्शन गतिविधियाँ चलाना और तकनीकी सहायता प्रदान करना। • सत्यापित परिणामों और प्रलेखित नवाचारों के आधार पर जिलों और परिवर्तनकर्ताओं (Changemakers) की तिमाही और वार्षिक मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए JEPC को शॉर्टलिस्ट की सिफारिश करना।

02. जिला समावेशन :

सितम्बर, 2025 से जिलों का DEIC में समावेशन किया जाएगा जिसका पहला आँकड़ा संग्रहण चक्र अक्टूबर में निर्धारित है (इस शैक्षणिक वर्ष की तीसरी तिमाही की शुरूआत से)। इस समावेशन में जिला और प्रखण्ड अधिकारियों का उन्मुखीकरण, KPIs के साथ संरेखण और ई–विद्यावाहिनी के आँकड़ा संग्रहण घटक के साथ उनकी मैपिंग, जिले के प्रदर्शन की प्रारंभिक बेंचमार्किंग और जिले द्वारा वर्ष–1 की प्राथमिकताओं की पहचान शामिल होगी :

चरण 1 जिला प्रशासनों द्वारा DEIC एसओपी (SOP) की समीक्षा

जिला नेतृत्व से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यान्वयन एसओपी की पूरी समीक्षा करें। ADPOs को जिला स्तर पर SPOC/नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। SPOCs आगे जिला और प्रखण्ड स्तर पर आँकड़ा और प्रशिक्षण प्रमुखों की पहचान करेंगे, जिससे कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु सुनिश्चित होंगे।

चरण 2 JEPC के नेतृत्व में जिला और प्रखण्ड अधिकारियों के साथ DEIC पर ब्रीफिंग सत्र

JEPC एक राज्य–स्तरीय ब्रीफिंग आयोजित करता है जिससे PMU प्रमुख कार्यक्रम तत्वों जैसे कि KPI और जिला मान्यता फ्रेमवर्क पर विस्तार से बताने, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं और प्रमुख अगले कदमों का विवरण देने और जिलों से स्पष्टीकरण की सुविधा प्रदान करने में सहयोग करता है।

चरण 3 JEPC के नेतृत्व में PMU समर्थित BRPs/CRPs का उन्मुखीकरण –

JEPC, BRPs और CRPs के लिए उन्मुखीकरण सत्र आयोजित करेगा जिसमें KPI डिक्शनरी प्रत्येक KPI की ई–विद्यावाहिनी मॉड्यूल से मैपिंग, आँकड़ा नियम और विद्यालय सहायता के लिए पहले महीने की अपेक्षाएँ शामिल होंगी। PMU मानकीकृत उन्मुखीकरण सामग्री (अद्यतन KPI नोट्स, eVV उन्मुखीकरण सामग्री, अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न) और तकनीकी अपडेट प्रदान करेगा और आवश्यकतानुसार सत्रों का सह–संचालन कर सकता है।

चरण 4 जिलों द्वारा तैयारी की जाँच (Readiness Checks) –

DEIC के लिए जिला SPOC तैयारी की जाँच सुनिश्चित करेगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि ई–विद्यावाहिनी ऐप सभी जिला, प्रखण्ड और क्लस्टर उपयोगकर्ताओं (BEEOs, BRPs, CRPs, शिक्षक और प्रधानाध्यापक) के लिए अद्यतन और कार्यात्मक है। जिले, विद्यालय सूचियों को BRP/CRP मार्गों से मैप करके और विजिट रोस्टर जारी करके, हर महीने 100% अद्वितीय विद्यालयों का कवरेज सुनिश्चित करेंगे। यह रोस्टर महीने के भीतर दोहरी विजिट (अनुमोदित फॉलो–अप को छोड़कर) को रोकेगा और छूटे हुए विद्यालयों से बचाएगा।

चरण 5 जिले के KPIs के आधार–रेखा प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं और कार्यान्वयन की पहली तिमाही के लिए मापने योग्य लक्ष्यों की पहचान करना –

नवीनतम तिमाही के आँकड़ों और किसी भी वैद्य ऐतिहासिक रेकॉर्ड का उपयोग करते हुए जिला KPIs के मुकाबले एक प्रारंभिक प्रदर्शन दृश्य संकलित करता है, इसे प्रखण्डों के साथ मान्य करता है और आने वाली तिमाही के लिए दो से तीन मापने योग्य प्राथमिकताओं का दस्तावेजीकरण करता है। प्रत्येक प्राथमिकता का एक स्वामी होता है, एक संक्षिपत कार्य सूची और एक लक्ष्य तिथि होती है जिससे हर तिमाही की एक स्पष्ट शुरूआत हो सके।

03. जिला आँकड़ा संग्रहण और KPI फ्रेमवर्क :

1. **आँकड़ा प्लेटफॉर्म :** प्रखण्ड और विद्यालय के अधिकारियों द्वारा आँकड़ा संग्रहण ई–विद्यावाहिनी (eVV) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त DEIC के तहत् स्वतंत्र तृतीय–पक्ष मूल्यांकन और अन्य राज्य कार्यक्रमों जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेशन, शिक्षक आवश्यकता मूल्यांकन और ''मेरा निपुण विद्यालय'' के आँकड़ों का भी लाभ उठाया जाएगा।

2. **आँकड़ा संग्रहण के माध्यम :** जिलों से आँकड़े दो प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त किए जाएँगे –
   a. BRPs/CRPs द्वारा विद्यालय भ्रमण और कक्षा–अवलोकन (जिसमें शिक्षण अभ्यास, विद्यालय प्रक्रियाएँ और सहायक स्थितियाँ शामिल हैं) और
   b. शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों द्वारा उपस्थिति और प्रासंगिक विद्यालय (जिसमें छात्र/शिक्षक उपस्थिति और eVV पर दर्ज अन्य नियमित विद्यालय आँकड़े) शामिल हैं।

3. **आँकड़ा संग्रहण की आवृत्ति :** विद्यालय भ्रमण और कक्षा अवलोकन मासिक होंगे। KPI डिक्शनरी में निर्दिष्ट अनुसार, अलग–अलग KPIs की रिर्पोटिंग आवृत्ति अलग–अलग हो सकती है – मासिक, तिमाही या अर्धवार्षिक।

4. **KPI फ्रेमवर्क :** नीचे दिया गया KPI फ्रेमवर्क उन संकेतकों, परिभाषाओं, स्रोतों और रिर्पोटिंग आवृत्तियों को निर्दिष्ट करता है जिनका उपयोग अके तहत् मापन के लिए किया जाएगा। प्रत्येक KPI को ई–विद्यावाहिनी से मैप किया गया है ताकि मानकीकृत भाजक और सत्यापन प्रोटोकॉल के साथ सभी जिलों में आँकड़ा संग्रहण में सुसंगतता सुनिश्चित हो सके। यह फ्रेमवर्क जिलों की स्कोरिंग, रैंकिंग और मान्यता के लिए एक सामान्य संदर्भ के रूप में काम करेगा।

विषय	KPI (प्रमुख प्रदर्शन संकेतक)	आवृत्ति	आँकड़ा स्रोत
आदान	सभी शिक्षण–अधिगम सामग्री प्राप्त करने वाले स्कूलों का प्रतिशत	मासिक (प्रत्येक वर्ष की पहली 2 तिमाही)	eVV : BRP/CRP द्वारा विद्यालय/कक्षा अवलोकन
	बुनियादी स्तर के लिए स्कूल पुस्तकालय में आयु–उपयुक्त पुस्तकों का उपयोग करने वाले स्कूलों का प्रतिशत	मासिक	
	प्रत्येक ग्रेड 1, 2 और 3 के लिए समर्पित कक्षा वाले स्कूलो का प्रतिशत	अर्धवार्षिक	
	एक महीने में >90% उपस्थिति वाले FLN ग्रेड के शिक्षकों का प्रतिशत	मासिक	eVV : शिक्षकों द्वारा स्वघोषित

	प्रिन्ट–समृद्ध कक्षाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत	अर्धवार्षिक	eVV : BRP/CRP द्वारा विद्यालय / कक्षा अवलोकन
कक्षा निर्देश	हैंडबुक में निर्धारित में निर्धारित संरचित पाठ योजना का पालन करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	मासिक	
	साक्षरता और संख्यात्मकता पर समर्पित समय के साथ सामान्य समय–सारणी का पालन करने वाले स्कूलों का प्रतिशत	मासिक	
	कक्षा में TLM का उपयोग करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	मासिक	
	रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के सीखने का आकलन करने वाले स्कूलों का प्रतिशत	मासिक	
	कक्षा में कम से कम एक सकारात्मक कक्षा प्रबंधन रणनीति का उपयोग करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	मासिक	
	अपने पाठ के दौरान समूह गतिविधियों को लागू करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	मासिक	
	शिक्षक आवश्यकता मूल्यांकन में मजबूत दक्षता प्रदर्शित करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	अर्धवार्षिक	JEPC द्वारा प्राप्त
	कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार ''मेरा विद्यालय निपुण'' के रूप में प्रमाणित स्कूलों का प्रतिशत	अर्धवार्षिक	
अभिभावक और छात्र संलग्नता	एक सप्ताह में >70% औसत छात्र उपस्थिति वाले स्कूलों का प्रतिशत	मासिक	eVV : शिक्षकों द्वारा स्वघोषित
	PTM में शामिल हुए अभिभावकों का प्रतिशत	तिमाही	eVV : BRP/CRP द्वारा विद्यालय / कक्षा अवलोकन
	स्कूल के नेताओं का प्रतिशत जो रिपोर्ट करते हैं कि पिछली PTM में शैक्षणिक और सामाजिक–भावनात्मक कल्याण के विषयों पर चर्चा की गई थी	तिमाही	
	प्रातः कालीन सभा में छात्र भागीदारी के साथ गतिविधियाँ आयोजित करने वाले स्कूलों का प्रतिशत	मासिक	
छात्र अधिगम	FLN और सामाजिक–भावनात्मक कल्याण परिणामों के तृतीय–पक्ष मूल्यांकन में छात्रों का प्रदर्शन	वार्षिक	तृतीय पक्ष मूल्यांकन का आँकड़ा
	FLN और सामाजिक–भावनात्मक कल्याण परिणामों के तृतीय–पक्ष मूल्यांकन में विशिष्ट लाभार्थी समूहों का प्रदर्शन	वार्षिक	

	निपुण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार "मैं भी निपुण" के रूप में प्रमाणित स्कूलों का प्रतिशत	तिमाही	JEPC द्वारा प्राप्त
	एक जिले में FLN चैंपियनशिप के लिए नामांकित स्कूलों का प्रतिशत	अर्धवार्षिक	

04. जिला मान्यता फ्रेमवर्क :

जिला मान्यता फ्रेमवर्क (DRF) वह प्रणाली है जिसके माध्यम से जिलों को DEIC के तहत् उनके प्रदर्शन और सुधार के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाता है। यह मानकीकृत करता है कि जिलों को कैसे स्कोर, रैंक और मान्यता दी जाती है, जिससे पूरे राज्य में तुलनात्मक और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

A. **मान्यता का दायरा और प्रकार :** जिला शिक्षा नवाचार चुनौती के तहत् मान्यता दो आयामों पर आधारित है –

a. प्रदर्शन आधारित मान्यता – KPI फ्रेमवर्क पर जिले के प्रदर्शन का मूल्यांकन, जिसे ई–विद्यावाहिनी के माध्यम से मापा जाता है और तृतीय–पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से मान्य किया जाता है।

b. अभ्यास आधारित मान्यता – परिवर्तनकर्ताओं और जिला स्पॉटलाईट्स की पहचान जो उन नवाचारों, स्थानीय समाधानों और नेतृत्व प्रथाओं को उजागर करते हैं जो जमीनी स्तर पर बेहतर FLN परिणामों में योगदान करते हैं।

B. **आवधिकता :** DRF के तहत् मान्यता दो स्तरों पर दी जाएगी, तिमाही एवं वार्षिक –

a. तिमाही मान्यता प्राप्त आँकड़ों पर आधारित होगी और इसके परिणामस्वरूप जिला लीडरबोर्ड और स्पॉटलाईट का प्रकाशन होगा।

a. वार्षिक मान्यता पूरे शैक्षणिक वर्ष के प्रदर्शन को समेकित करेगी। इससे तृतीय–पक्ष द्वारा मूल्यांकन परिणाम आँकड़े शामिल होंगे और इसका समापन वार्षिक राज्य–स्तरीय मान्यता और एक्सपोजर यात्राओं के रूप में होगा।

C. **प्रदर्शन आधारित मान्यता :** इस श्रेणी के तहत् मान्यता DEIC DPI फ्रेमवर्क पर आधारित है। जिलों को तिमाही और वार्षिक आधार पर आउटपुट और परिणाम संकेतकों पर प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जाएगा। प्रत्येक KPI का एक निर्धारित भार होगा और जिला स्कोर की गणना ई–विद्यावाहिनी के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करके की जाएगी और जहाँ लागू हो, तृतीय–पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से मान्य किया जाएगा।

a. **संकेतक स्कोरिंग :** प्रत्येक KPI को, प्रत्येक जिले के लिए परिभाषित संकेतक के मुकाबले उसके निरपेक्ष प्रदर्शन के आधार पर स्कोर किया जाएगा।

b. **समग्र सकोरिंग :** प्रत्येक जिले के लिए एक समग्र स्कोर बनाने के लिए अधिसूचित भार का उपयोग करके सभी KPIs के स्कोर को एकत्रित किया जाएगा। संकेतकों और जिलों के आधार–रेखाओं में तुलनीयता की अनुमति देने के लिए आँकड़ों को सामान्यीकरण किया जाएगा।

c. **जिलों की रैंकिंग :**

i. जिलों को दो मापदण्डों पर रैंक किया जाएगा – (क) समग्र स्कोर पर आधारित निरपेक्ष प्रदर्शन और (ख) पिछली तिमाही की तुलना में सुधार।

ii. रैंकिंग KPI फ्रेमवर्क प्रत्येक वर्टिकल और समग्र स्कोर, दोनों के लिए तैयार की जाएगी।

iii. अंतिम रैंकिंग अधिसूचित विधि का उपयोग करके प्रदर्शन और सुधार को मिलाकर जारी की जाएगी।

iv. JEPC विस्तृत कार्यप्रणाली और गणना फ्रेमवर्क को अलग से अधिसूचित करेगा जिसमे संकेतक भार, सामान्यीकरण प्रोटोकॉल और प्रदर्शन तथा सुधार स्कोर को जोड़ने का सूत्र शामिल है।

v. प्रदर्शन आधारित मान्यता श्रेणियाँ – KPI फ्रेमवर्क पर जिले के प्रदर्शन द्वारा निर्धारित, निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदर्शन–आधारित मान्यता प्रदान की जाएगी।

d. **प्रदर्शन आधारित मान्यता श्रेणियाँ :** प्रदर्शन आधारित मान्यता निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान की जाएगी, जो KPI फ्रेमवर्क पर जिले के प्रदर्शन द्वारा निर्धारित होती है –

श्रेणी	मान्यता का आधार	आवृत्ति
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले	KPI फ्रेमवर्क पर उच्चतम समग्र स्कोर वाले जिले	तिमाही और वार्षिक
सर्वाधिक सुधार करने वाले जिले	पिछली तिमाही/वर्ष की तुलना में सबसे अधिक सुधार दिखाने वाले जिले	तिमाही और वार्षिक
वर्टिकल उत्कृष्टता पुरस्कार	JEPC द्वारा अधिसूचित अनुसार, विशिष्ट KPI वर्टिकल (जैसे सीखने के परिणाम, शिक्षण अभ्यास, बुनियादी ढ़ाँचा) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले	वार्षिक

D. **अभ्यास आधारित मान्यता श्रेणियाँ :** अभ्यास आधारित मान्यता जिला और विद्यालय दोनों स्तरों पर स्थानीयकृत नवीन प्रथाओं और नेतृत्व के प्रयासों को उजागर करेगी। यह मात्रात्मक प्रदर्शन मैट्रिक्स से आगे जाती है और नवाचार, अनुकरणीय समस्या–समाधान

और उत्कृष्ट नेतृत्व के प्रयासों की कहानियों को सामने लाती है, जो अन्य जिलों को भी प्रेरित कर सकती है।

a. **अभ्यास आधारित मान्यता श्रेणियों के प्रकार :**

i. जिला स्पॉटलाईट्स : DRF से विजेता जिलों की ''जिला प्रोफाइल'' राज्य स्तरीय मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। एक ''जिला प्रोफाइल'' में नीचे दिए गए 3 तत्वों में से सभी या कुछ का संयोजन हो सकता है –

(क) **नवाचार स्पॉटलाईट्स :** तिमाही के दौरान जिले द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट स्थानीय नवाचारों और प्रभावशाली प्रथाओं पर प्रकाश डालना, जिन्होंने KPI प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान दिया हो।

(ख) **सफलता की कहानी :** तिमाही के दौरान जिले से 1 से 2 सबसे प्रभावशाली सफलता की कहानियों या सफल उपलब्धियों का प्रदर्शन करना।

(ग) **कार्मिक प्रोफाइल :** JEPC और जिला नेतृत्व की आम सहमति के आधार पर एक जिला स्तरीय अधिकारी (DEO, DSE, DPO, ADPO, आदि) को ''कार्मिक प्रोफाइल'' के माध्यम से स्पॉटलाईट किया जाएगा। इसमें एक शिक्षा अधिकारी के रूप में उनकी यात्रा, प्रमुख करयिर उपलब्धियाँ और योगदान, नेतृत्व शैली और दृष्टिकोण, जिले के लिए उनकी दृष्टि और बहुत कुछ शामिल होगा।

ii. विद्यालय स्तरीय या चेंजमेकर स्पॉटलाईट्स : सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय स्तर पर उन उत्कृष्ट नवाचारों के लिए मान्यता दी जाएगी, जिनका छात्रों के सीखने के परिणामों और सामाजिक–भावनात्वक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। नवाचारों को 3 व्यापक श्रेणियों में मान्यता दी जाएगी :

(क) **कक्षा उत्प्रेरक (Classroom Catalyst) :** नवीन शिक्षण विधियों और कक्षा की शैक्षणिक प्रथाओं के लिए।

(ख) **कल्याण चैंपियन (Wellbeing Champion) :** उन नवाचारों के लिए जो छात्र के सामाजिक–भावनात्मक कल्याण का पोषण करते हैं, एक बेहतर विद्यालय का परिवेश बनाते हैं और विद्यालय में छात्र जुड़ाव को बढ़ाते हैं।

(ग) **कक्षा से परे (Beyond the Classroom) :** उन नवाचारों के लिए जो क्षेत्र भ्रमण, अनुभावनात्मक शिक्षा सह पाठ्यक्रम जुड़ाव और अन्य रचनात्मक गतिविधि–आधारित सीखने के माध्यम से सीखने को पारंपरिक कक्षा से बाहर ले जाते हैं।

b. **जिला और चेंजमेकर स्पॉटलाईट्स की पहचान करने की प्रक्रिया :**

i. **जिला स्पॉटलाईट्स की पहचान :** DRF से विजेता जिले अपने–अपने जिलों से प्रमुख नवाचारों और प्रभाव की कहानियों का चयन करेंगे और JEPC द्वारा साझा किए जाने वाले एक नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

ii. **चेंजमेकर स्पॉटलाईट्स की पहचान :** सभी जिलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के नवाचारों को स्व–नामांकन या BRPs की सिफारिश के माध्यम से जिला प्रशासनों को भेजा जा सकता है। एक जिला–स्तरीय समिति सभी विद्यालय और जिला स्तर की प्रस्तुतियों का चार मानदण्डों पर मूल्यांकन करेगी – व्यवहार्यता, प्रभाव, विस्तारशीलता और स्थिरता। आगे के विचार के लिए 2–5 प्रस्तुतियों को अंतिम रूप देगी।

iii. **PMU द्वारा शॉटलिस्टिंग और क्षेत्र सत्यापन :** PMU प्रस्तुत नवाचारों का आकलन करेगा, शीर्ष उम्मीदवारों को शॉटलिस्ट करेगा और प्रथाओं को सत्यापित करने के लिए जहाँ आवश्यक हो, क्षेत्र भ्रमण करेगा।

iv. **मान्यता और प्रवर्धन (Amplification) :** अंतिम चयनों को राज्य–स्तरीय चैनलों, समाचार पत्रिकाओं और भागीदारी एनजीओ प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा ताकि नवाचारों को उजागर किया जा सके और जिलों में उनकी प्रतिकृति (replicaiton) को प्रेरित किया जा सके।

05. मार्गदर्शन तंत्र :

KPI प्रगति में सुधार करने और सीखने के परिणाम प्राप्त करने के लिए जिलों को लक्षित क्षमता निर्माण हेतु मार्गदर्शन गतिविधियों और सीखने के संसाधनों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी। वे अधिकतर प्रत्येक जिले के संदर्भ के अनुरूप होंगे और पहचानी गई चुनौतियों या आवश्यकता के आधार पर अनुकूलित (customized) सहायता प्रदान करेंगे।

(A) उपलब्ध मार्गदर्शन तंत्र के प्रकार :–

1. **मासिक प्रदर्शन समीक्षा :** –
   a. हर महीने JEPC और PMU, जिला नेतृत्व को प्रतिक्रिया (feedback) और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए सभी जिलों के KPI प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। इस पर जिला नेतृत्व के साथ मासिक JEPC बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी।
   b. प्रत्येक जिले को हर महीन एक प्रगति दृश्यता पत्रक (progress visibility sheet) या एक जिला रिपोर्ट कार्ड प्राप्त होगा, जिसमें उनके KPI प्रदर्शन को व्यवस्थित तरीके से उजागर किया जाएगा।

2. **रणनीतिक बैठकें (द्विवार्षिक) :** –

a. हर 6 महीने में JEPC, PMU और संबंधित जिला नेतृत्व के बीच एक व्यक्तिगत रणनीतिक बैठक आयोजित की जाएगी।

b. इस बैठक का उपयोग कार्यान्वयन में कमियों को समझने और सुधार की गुंजाइश की पहचान करने के लिए KPIs पर जिले के प्रदर्शन की गहन रणनीतिक समीक्षा करने हेतु किया जाएगा।

c. जिले इन्हें संयुक्त समस्या–समाधान सत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं ताकि वे उन लक्षित नवाचारों का निर्धारण कर सकें जिन्हें वे अपना सकते हैं।

3. **कार्यशालाएँ और सीखने के सत्र :** –

a. जिलों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के नेतृत्व में आवधिक कार्यशालाएँ या पैनल चर्चाएँ आयोजित की जाएगी।

b. अन्तर जिला ज्ञान साझाकरण और सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए क्यूरेटेड सहकर्मी–शिक्षण सत्रों की सुविधा प्रदान की जाएगी।

c. सीखने के लिए सभी विषयों को सबसे प्रासंगिक और लक्षित क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलों के KPI रूझानों का विश्लेषण करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

(B) जिलों को अन्य सामान्यीकृत सहायता भी उपलब्ध होगी :–

1. **सीखने के संसाधन :** – FLN और SLN संसाधनों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी। इस मॉड्यूल में गाईड, केस स्टडी, शोध पत्र, विडियो एक्सप्लेनर और अन्य संसाधन शामिल हो सकते हैं।

2. **रणनीतिक सलाह के लिए विशेषज्ञ पैनल :** – PMU एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित करेगा जिसमें विशेषज्ञ, पूर्व जिला प्रशासक और अन्य प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह पैनल –

a. आवश्यकता के आधार पर जिलों को विशिष्ट प्रश्नों और कार्यान्वयन चुनौतियों पर एक–एक करके रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

b. इसमें FLN NGO प्रमुख अभ्यासकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों (शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों) और अनुभवी पूर्व सरकारी अधिकारियों जैसे सदस्य शामिल होंगे।

c. आवधिक DEIC सीखने की कार्यशालाओं में भाग लेना, जहाँ व्यापक हितधारक (जैसे BRPs, CRPs, शिक्षक) भी विशेषज्ञ अंतदृष्टि से जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं।

District Education Innovation Challenge (DEIC)

District Implementation SOP

January 2026

LiftEd Transforming Foundational Literacy and Numeracy

Contents

PART A – Background and Context of DEIC:

01 – About DEIC

02 – Scope and Key Design Principles

PART B – District Implementation SOP

01 – Roles and Responsibilities of Key Stakeholders

02 – District Onboarding

03 – Data Collection and KPI Framework

04 – District Recognition Framework (DRF)

05 – District Guidance Mechanisms

Part A - Background and Context of DEIC

01. The District Education Innovation Challenge

The LiftEd District Education Innovation Challenge (DEIC) is a challenge-based programme that aims to build momentum for FLN outcomes in Jharkhand by promoting micro-innovation, championing data-driven governance, and rewarding performance improvements across all districts. DEIC will be implemented by JEPC with support from LiftEd DEIC consortium consisting of The Matri Trust, Porticus Foundation, The British Asian Trust, Dalberg Advisors and Room to Read India Trust.

DEIC aims to create a larger systemic change in the state, by catalyzing action within the government machinery resulting in:

1. **Higher FLN outcomes in the short & long term:** DEIC will provide greater impetus to Jharkhand districts to improve FLN outcomes by implementation of proven levers, fostering healthy competition and by leveraging rewards and recognition as incentives.
2. **Improved capacity of district officials**: Under DEIC, District officials in JH (e.g., District Education Officer, District Project Coordinators) will interact with experts and participate in learning trips, building their capacity for innovative thinking, leadership and effective execution leading to improved administrative capacity. This will strengthen the state's foundation and make it capable of adopting and driving the DEIC model independently.
3. **Improved FLN data collection and analysis systems:** DEIC will provide additional impetus and support to the JH state government to refine and improve the quality, efficiency and reliability of FLN outcomes data infrastructure & collection system, and accelerate their adoption at a state-wide level, to help improve data reliability.
4. **Facilitate assessment:** The challenge will build the state's assessment capacity by helping identify KPIs that are the best indicators of FLN improvement and build the capacity of the state to assess them.
5. **JH becomes a model state:** JH can serve as inspiration for other states to adopt an FLN challenge, positioning as a pioneer. Publicity can attract more foundations, philanthropists, and other investors to learn from its experience in other states/geographies (e.g., Aspirational Districts)

02. Scope and Key Design Principles

Scope	**Details**
Coverage	All 24 districts in the state
Timeline	3 years – Academic Year 2025-26 to 2027-28
Implementing Body	Jharkhand Education Project Council
Supporting Organizations	Founding Partners: The Maitri Trust and Porticus Foundation;

	Program Leader: The British Asian Trust; Performance Manager: Dalberg Advisors; and Technical Partner: Room to Read India Trust
Target Stakeholders	1. District Education Officials such as DEOs, DSEs, and ADPOs 2. Block level education officials such as BEEOs, Block Resource Persons, and Cluster Resource Persons, 3. School Leaders such as Head Masters, and Teachers.
Thematic Focus	Foundational Literacy and Numeracy + School Climate

The objective of the District Education Innovation Challenge (DEIC) is to enhance foundational literacy and numeracy and school climate, by empowering district-level leadership with data-backed evidence on their performance. DEIC has been designed around three core principles: **Momentum**, **Visibility**, and **Guidance**.

A. Momentum

DEIC is designed to build and sustain momentum among districts by linking recognition to measurable, verifiable data backed performance. The initiative seeks to channel the energy of district administrations towards clear priorities in FLN and school climate, while celebrating progress in a transparent, data-driven manner.

It will involve all key district leaders (District Collector, DEOs, ADPOs, DSEs) as well as recognize efforts at all levels (block, school, etc), on a quarterly and annual basis. To measure district performance, DEIC will track Key Performance Indicators that have been prioritized across FLN and School Climate and measure them using DEIC's District Recognition Framework.

A.1 Key Performance Indicators Framework

Districts will be measured against a structured framework comprising **17 Key Performance Indicators (KPIs)**, covering Inputs, Classroom Instruction, and Community Engagement and 4 Outcome Indicators measuring student learning and school climate. This data will be collected from the eVV app, UDISE+ data and other sources. The KPI framework may be refined annually, based on progress observed and inputs from on-ground stakeholders, to ensure continued relevance and effectiveness.

A. 2 District Recognition Framework

Each KPI will be measured and ranked through the District Recognition Framework, calculated both quarterly and annually. A structured system of rewards will be instituted for districts on a quarterly and annual basis that are recognized from the District Recognition Framework. Teachers with standout innovations will also be rewarded to acknowledge progress and sustained efforts towards program goals. Recognition mechanisms may include, but are not limited to

- Public leaderboards showcasing performance
- Case profiles for high performing districts and teachers
- Opportunities for learning visits to enable peer learning

- Other forms of acknowledgment designed to foster motivation, celebrate achievements, and encourage a culture of healthy competition and continuous improvement.

B. Visibility

The Visibility principle ensures that district administrations have transparent and timely access to data on their performance. It focuses on continuous monitoring, credible assessments, and actionable insights for course correction. To establish visibility, DEIC will make use of data on KPIs collected over eVV, present them on monthly progress reports or scorecards for the districts. Along with it, annual assessments on FLN and school climate outcomes also provide visibility of progress at an outcome level for districts.

B.1. Data Collection via eVidya Vahini app

The e-VidyaVahini (eVV) application, an ICT-based platform developed by the State, shall serve as the primary tool for real-time school-level data collection under DEIC. Data will be captured through Block Resource Persons (BRPs) and Cluster Resource Persons (CRPs) during routine school monitoring visits and by Teachers and Headmasters. Further, independent assessments from other state programmes such as School Certification and Teachers Needs Assessments and Mera Nipun Vidyalaya will be leveraged for pertinent DEIC KPIs

B.2. Annual Third-party Assessments

Independent third-party assessments shall be conducted annually to provide an objective evaluation of district performance. The assessment will cover FLN learning outcomes and school climate/ whole child development outcomes. It will build on quarterly monitoring data (outputs) to provide a holistic picture of district performance over the academic year. District-level and state-level reports will be prepared and shared with stakeholders, presenting performance trends, key findings, and improvement areas.

B.3. Monthly Scorecards (Progress Visibility)

Districts will receive monthly scorecards summarising performance across all DEIC KPIs. They will include data on District's current performance, progress since previous cycle, peer benchmarks to encourage healthy competition and learning.

C. Guidance

Through the course of DEIC, districts will be provided with **targeted, strategic guidance** based on their KPI performance, to help them understand their progress, identify areas requiring improvement as well as practices worth sustaining or scaling, receive advisory inputs from JEPC and the DEIC Performance Management Unit to plan and execute targeted interventions.

C.1 Guidance Activities: Examples of guidance mechanisms made available to districts include:

- **Monthly Review Meetings** to track performance trends and discuss quick corrective measures.
- **Bi-Annual 1:1 Strategic Check-ins** between district leadership and the JEPC/ PMU team to review progress in depth and problem solve for emerging challenges.

- **Expert-Led Workshops and Learning Sessions** to provide technical know-how, share best practices, and foster peer learning across districts.

C.2 Learning Resources: Beyond the guidance activities, there are other state support resources that are available to the districts to access on a need basis:

- **Learning resources**: Includes guides, case studies, FLN primers, and leadership modules, drawing both from DEIC learnings and proven practices from other states and contexts.
- **Access to experts**: A panel of experts can be made available to districts for ongoing or on-demand support, the panel will likely include experts from non-governmental organisations, education sector experts, ex district officials, etc.

Part B – District Implementation SOP

01. Roles and Responsibilities of Key Stakeholders:

The District Education Innovation Challenge will be led by the Jharkhand Education Project Council (JEPC) and implemented through coordinated action across districts and blocks, with technical support from the DEIC PMU. The roles and responsibilities of each stakeholder are as follows:

Stakeholder	Key Roles & Responsibilities
JEPC	• Issue guidelines, strategy, and implementation framework for DEIC • Deploy robust data-collection process by refining stakeholder modules on e-Vidya Vahini (eVV) • Convene state-level DEIC review to review DEIC performance; set priorities and communicate decisions to districts and blocks • Undertake quarterly and annual recognition of districts and changemakers • Ensure convergence with other state initiatives and align program calendars
Districts Administration	• Integrate and prioritise DEIC within the district FLN agenda and monthly review schedule • ADPOs are to be nominated as nodal officers for DEIC and ensure programme readiness • Build capacity of block officials, head teachers and teachers on KPIs, data quality and use of results • Conduct monthly reviews under the chairmanship of the Deputy Commissioner, on district level performance under DEIC • Identify areas of improvement and district priorities, explore opportunities for innovation to improve outcomes • Recognise local innovations and nominate cases for state recognition and spotlights, scale proven practices within districts
Block Administration	• Translate district priorities into a block implementation plan with clear cluster and school targets • Conduct monthly reviews under the chairmanship of the Block Education Extension Officer, on block level performance under DEIC

	• Ensure complete and timely school-level data capture by BRPs, CRPs, and teachers, on e-Vidya Vahini each month • Conduct cluster-level reviews on DEIC performance, issue actions and track closure • Build capacity of cluster officials and school teams on KPIs, data quality and use of results • Identify and document block-level innovations and changemakers; nominate for district and state recognition; enable peer learning across clusters
PMU	• Serve as the technical and programme-management backbone for DEIC • Develop and maintain SOPs, tools, templates and orientation materials for districts and blocks • Orient officials at state, district and block levels. • Monitor data quality and recommend refinements to improve data collection and validation processes • Produce monthly scorecards entailing district and block performance on DEIC and associated dashboards. • Run district guidance activities and provide technical assistance. • Recommend recognition shortlists to JEPC for facilitating quarterly and annual recognition of districts and changemakers based on verified results and documented innovations.

02. District Onboarding

Starting September 2025, districts will be onboarded onto DEIC, with the first data collection cycle scheduled October, (start of Quarter 3 onwards of this academic year). Onboarding will comprise of orientation of district and block officials, alignment with KPIs and their mapping with e-Vidya Vahini data collection modules, initial benchmarking of district performance and identification of Y1 priorities by the district:

1. Step 1: Review of DEIC SOP by District Administrations and nomination of SPOCs

   The District leadership is expected to review the Implementation SOP in full. ADPOs will be designated SPOC/ nodal officers at the district level. The SPOCs further identify data and training lead at district and block levels, ensuring clear points of contact for implementation.

2. Step 2: Briefing session on DEIC led by JEPC with District and Block officials

   JEPC convenes a state-led briefing, with the PMU supporting in elaborating on the key programme elements such as KPI and District Recognition Frameworks, detailing implementation processes and key next steps, and facilitating clarifications from the districts.

3. Step 3: Orientation of BRPs/CRPs led by JEPC and supported by PMU

   JEPC will conduct orientation sessions for BRPs and CRPs covering the KPI dictionary, the mapping of each KPI to e-Vidya Vahini modules, data rules, and first-month expectations for school support. The PMU will provide standardized orientation materials (updated KPI notes,

eVV orientation materials, FAQs) and technical updates and may co-facilitate sessions as required.

4. Step 4: Districts undertake readiness checks

   District SPOC for DEIC will ensure readiness checks to confirm that the e-Vidya Vahini app is updated and functional for all district, block and cluster users (BEEOs, BRPs, CRPs, Teachers and HMs). Districts will ensure 100% coverage of unique schools every month by mapping school lists to BRP/CRP routes and issuing visit rosters that prevent duplicate visits within the month (except approved follow-ups) and avoid missed schools.

5. Step 5: Districts review initial benchmarking of district performance and identify measurable targets for first quarter of implementation

   Using the latest quarter's data and any valid historical records, the district compiles an initial performance view against the KPIs, validates it with blocks, and documents two to three measurable priorities for the coming quarter. Each priority has an owner, a short action list and a target date, enabling a clear start to the October cycle.

03. District Data Collection and KPI Framework

1. **Data Platform:** Data collection by Block and School Officials will be anchored on the e-Vidya Vahini (eVV) platform. Additionally, data from independent third-party assessments under DEIC and other state programmes such as School Certification and Teachers Needs Assessments and Mera Nipun Vidyalaya will be leveraged.

2. **Sources of data collection:** Data from Districts will be captured from two primary sources:
   a. School visits and classroom observations by BRPs/CRPs (including instructional practice, school processes and enabling conditions), and
   b. Attendance and relevant school records by teachers/head teachers (including student/teacher attendance and other routine school data recorded on eVV).

3. **Frequency of Data Collection:** School visits and classroom observations will be monthly. Individual KPIs may have different reporting frequencies, monthly, quarterly, or semi-annual, as specified in the KPI dictionary.

4. **KPI Framework:** The KPI Framework below specifies the indicators, definitions, sources, and reporting frequencies that will be used for measurement under DEIC. Each KPI has been mapped to modules on e-Vidya Vahini to ensure consistency in data capture across districts, with standardised denominators and validation protocols. This framework will serve as the common reference for scoring, ranking, and recognition of districts.

Theme	KPI	Frequency	Data Source

Inputs	% of schools receiving all teaching learning materials	Monthly *(First 2 quarters each year)*	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of schools using age-appropriate books in school library for foundational level	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of schools having dedicated classrooms for each grade 1, 2, and 3	Half-yearly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of teachers in FLN Grades with >90% attendance in a month	Monthly	eVV *Teachers – self reported*
	% of schools with print rich classrooms	Half-yearly	eVV *BRP/CRP spot visits*
Classroom Instruction	% of teachers following structured lesson plan, as prescribed in the handbook	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of schools following common timetable with dedicated time on Literacy & Numeracy	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of teachers using TLMs in the classroom	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of schools assessing students' learning through formative assessments	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of teachers using at least one positive classroom mgmt. strategy in class*	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of teachers implementing group activities during their lesson	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of teachers who showcase strong proficiency in Teacher Needs Assessments	Half-yearly	*Data collected from Teachers Needs Assessment by JEPC*
	% of schools certified as "Mera Vidyalay NIPUN" as per the program guidelines	Half-yearly	*Data collected from "Mera Vidyalay NIPUN" by JEPC*
Parent and Student Engagement	% of schools with >70% average student attendance in a week	Monthly	eVV *Teachers – self reported*
	% of parents that attended the PTM	Quarterly	eVV *BRP/CRP spot visits*
	% of school leaders reporting that academic, non-academic and socio-emotional wellbeing topics were discussed in the last PTM	Quarterly	eVV *BRP/CRP spot visits*

	% of schools conducting activities with student participation in the morning assembly	Monthly	eVV *BRP/CRP spot visits*
Student Learning	Performance of students in third-party assessments of FLN and Socio-emotional well-being outcomes	Annually	Third party assessments
	Performance of specific beneficiary groups in third-party assessments on FLN and Socio-emotional well-being outcomes	Annually	Third party assessments
	% of schools certified as "Mai Bhi NIPUN" as per the NIPUN program guidelines	Quarterly	Mai Bhi NIPUN results
	% schools in a district nominated for FLN championship	Half-yearly	FLN Championship Program results

04. District Recognition Framework

The District Recognition Framework (DRF) is the system through which districts are formally acknowledged for their performance and improvement under DEIC. It standardises how districts are scored, ranked, and recognised, ensuring comparability and transparency across the state.

1. **Scope and types of recognition:** Recognition under the District Education Innovation Challenge is based on two dimensions:
    a. Performance-based recognition: assessment of district performance on the KPI Framework, measured through e-Vidya Vahini and validated through third-party evaluation.
    b. Practice-based recognition: identification of changemakers and district spotlights that highlight innovations, local solutions, and leadership practices contributing to improved FLN outcomes on the ground.

2. **Cadence:** Recognition under the DRF will be undertaken at two levels: quarterly and annual.
    a. Quarterly recognition will be based on data captured and will result in publication of district leaderboards and spotlights.
    b. Annual recognition will consolidate performance across the academic year, incorporate third-party evaluated outcomes data, and will culminate into annual state-level recognition and exposure visits

3. **Performance Based Recognition**: Recognition under this category anchors upon the DEIC KPI Framework. District will be ranked based on performance on output and outcome indicators on a quarterly and annual basis. Each KPI will carry a defined weight, and district

scores will be computed using data captured through e-Vidya Vahini and validated through third-party assessments where applicable

a. Indicator Scoring: Each KPI will be scored for every district based on its absolute performance against the defined indicator.

b. Composite Scoring: Scores across KPIs will be aggregated using the notified weights to generate a composite score for each district. Data will be normalised to allow comparability across indicators and across district baselines.

c. Ranking Districts:

   i. Districts will be ranked on two parameters (i) absolute performance based on the composite score, and (ii) improvement compared to the previous quarter.

   ii. Rankings will be generated both for each KPI vertical and for the overall composite score.

   iii. Final rankings will be issued by combining performance and improvement using the notified method.

   iv. JEPC will notify the detailed methodology and calculation framework separately, including indicator weights, normalization protocols, and the formula for combining performance and improvement scores.

d. Performance Based Recognition Categories: Performance-based recognition will be conferred across the following categories, determined by district performance on the KPI Framework:

Category	Basis of Recognition	Frequency
Top Performing Districts	Districts with the highest composite scores on the KPI Framework	Quarterly & Annual
Most Improved Districts	Districts showing the greatest improvement compared to the previous quarter/year	Quarterly & Annual
Vertical Excellence Awards	Districts demonstrating outstanding performance in specific KPI verticals (e.g., Learning Outcomes, Teaching Practices, Infrastructure), as notified by JEPC	Annual

4. **Practice Based Recognition categories:** Practice based recognition will highlight localized innovative practices and leadership efforts, at both District and School levels**.** It goes beyond quantitative performance metrics and captures stories of innovation, exemplary problem solving, and standout leadership efforts that can inspire other districts too.

   a. Types of Practiced Based Recognition Categories:

i. District Spotlights: Winning districts from DRF will have their District Profile published through state level media channels. A District Profile can consist of all or a combination of the below 3 elements:

   a. Innovation Spotlight: Highlighting the standout local innovations and impactful practices that were adopted by the district, during the quarter, and may have contributed to increased KPI performance.

   b. Success Story: Showcasing 1 to 2 most impactful success stories or breakthrough achievements from the district, during the quarter.

   c. Personnel Profile: Based on consensus from JEPC and the district leadership, one district level official (DEO, DSE, DPO, ADPO, etc) will be spotlighted through a Personnel Profile. It will include their journey as an education officer, key career achievements and contributions, leadership style and approach, their vision for the district, and more.

ii. School Level or Changemaker Spotlights**:** Teachers and Headmasters from government schools will be recognized for standout innovations at the school level that has an impact on students' learning outcomes and socioemotional wellbeing. Innovations will be recognized across the 3 broad categories:

   a. Classroom Catalyst: for innovative teaching methods and classroom pedagogical practices

   b. Wellbeing Champion: for innovations that nurture the student's socioemotional wellbeing, create a better school climate and student engagement in school

   c. Beyond the Classroom: for innovations that take learning outside the conventional classroom through field visits, experiential learning, co-curricular engagement, and other creative activity-based learning

b. Process of Identifying District and Changemaker Spotlights:

   i. Identifying District Spotlights: Winning districts from DRF will select prominent innovations and impact stories from their respective districts and provide necessary information in a nomination form which will be shared by JEPC.

   ii. Identifying Changemaker Spotlights: Innovations from teachers and headmasters from all districts can be sent via self-nomination or BRPs recommendation, to the district administrations. A district-level committee will evaluate all school and district level submissions on four criteria – feasibility, impact, scalability, and sustainability. and finalize 2–5 submissions for further consideration.

iii. PMU Shortlisting & Field Validation: The PMU will assess the submitted innovations, shortlist top candidates, and conduct field visits where necessary to validate practices.

iv. Recognition & Amplification: Final selections will be published through state-level channels, newsletters, and partner NGO platforms to spotlight innovations and inspire replication across districts.

05. Guidance Mechanisms

A series of guidance activities and learning resources will be available to the districts for targeted capacity building, in order to improve KPI progress and achieve learning outcomes. They will mostly be tailored to the context of each district and provide customized support based on the identified challenges or need.

1. **Types of guidance mechanisms available:**
    a. Monthly performance review:
        i. Every month JEPC and PMU will review KPI performance of all districts to offer feedback and strategic direction to the district leadership. This will be discussed during the monthly JEPC meeting with the district leadership.
        ii. Each district will receive a progress visibility sheet or a district report card, each month, highlighting their KPI performance in a systematic manner.

    b. 1:1 Strategic Check-ins (bi-annual):
        i. Every 6 months, an in-person strategic check-in will be held between JEPC, PMU and the respective district leadership.
        ii. The check-in will be leveraged to do an in-depth strategic review of the district's performance on KPIs to understand gaps in implementation and identify further room for improvement.
        iii. Districts can use them as joint problem-solving sessions to determine targeted innovations they can undertake.

    c. Workshops and Learning Sessions:
        i. Periodic workshops or panel discussions led by sector experts will be conducted to address key challenges faced by districts
        ii. Curated peer-learning sessions will be facilitated to encourage cross-district knowledge sharing and learning
        iii. All topics for learning will be finalized after analyzing KPI trends across districts to ensure the most relevant and targeted capacity building

2. **Other generalized support will also be available to the districts:**

a. Learning resources: A range of FLN and SEL resources will be made available. These may include guides, case studies, research papers, video explainers and other resources. Following is an indicative and non-exhaustive list of topics covered:

b. Expert panel for strategic advisory: PMU will establish an Expert Panel comprising of specialists, past district administrators, and other eminent experts. The panel will:

i. Provide one-on-one strategic guidance to districts on specific queries and implementation challenges, on a need basis.

ii. Include members such as leading FLN NGO practitioners, subject matter experts (researchers and academics), and experienced former government officials.

iii. Participate in periodic DEIC learning workshops, where broader stakeholders (e.g., BRPs, CRPs, teachers) can also engage and learn from expert insights.